बदलेगी रेडलाइट एरिया की तस्वीर

परचम और महिला विकास निगम ने राज्य के 25 रेडलाइट एरिया का पूरा किया सर्वे

अनामिका

मुजफ्फरपुर

स्याह गलियों की जिन्दगी शौक नहीं रेड लाइट एरिया के लोगों की मजबूरी है। इनकी विकल्पहीन दुनिया में परम्पराओं को तोड़ने का तरीका महिलाएं नहीं ढूंढ़ पा रही हैं। बच्चे पहचान के संकट में फंसे हैं और युवाओं को ढंग का रोजगार मयस्सर नहीं। सर्वेक्षण रिपोर्ट यही कहती है। और अब यहां के लोगों की यह दिन-दुनिया बदलने वाली है। इसके लिए जारी कवायद का फर्स्ट स्टेज पूरा हो गया है।

महिला विकास निगम और परचम नामक संस्था के संयुक्त प्रयास से रेड लाइट एरिया में चल रहा सर्वेक्षण पूरा कर लिया गया हैं। रिपोर्ट शीघ्र राज्य सरकार को सौंपी जाएगी जिसके आधार पर नर्तकियों व उनके परिवार के विकास व आरक्षण संबंधी रणनीति बनाई जाएगी। सर्वे का निष्कर्ष अभी सार्वजनिक नहीं किया गया। हालांकि जो महत्वपूर्ण बातें छनकर आयीं हैं उसके मुताबिक यहां महिलाएं कोई और रास्ता न मिल पाने के कारण दूसरी दुनिया में कदम नहीं रख पा रही हैं। 60 फीसदी बच्चे यहां से स्कूल नहीं जाते हैं। जो जाते हैं, उन्हें पहचान छिपाकर पढ़ाई करनी पड़ती है। यहां के 50 फीसदी से ज्यादा युवा पढ़ने-लिखने के बाद भी मेन स्ट्रीम के रोजगार या नौकरी में नहीं जा पाते हैं। अंततः उन्हें भी यहीं खप जाना पड़ता है। उल्लेखनीय है कि इनके विकास व आरक्षण को अंतिम स्वरुप देने के लिए महिला विकास निगम और परचम ने राज्य के 25 रेडलाइट एरिया का सर्वे पूरा कर लिया है। सर्वे छह माह तक चला। इसकी रिपोर्ट इस महीने मुख्यमंत्री को सौंपी जाएगी। सर्वे मुजफ्फरपुर समेत सीतामढ़ी, सहरसा, पूर्णिया आदि जिलों में किया गया है।

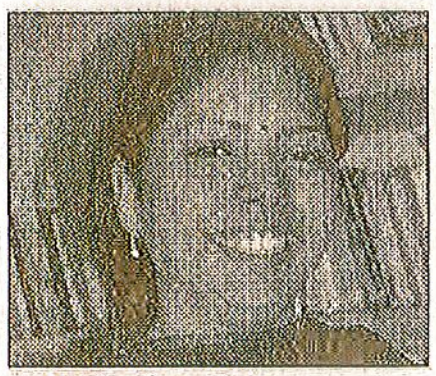

परचम की सचिव नसीमा

बेहतर भविष्य के लिए

- रेडलाइट एरिया के बच्चों को छात्रवृत्ति के साथ प्राइमरी, हायर एजुकेशन में मिले विशेष कोटा
- यहां की बुजुर्ग महिलाओं को मिले पेंशन, युवा वर्ग को मिले नौकरियों में आरक्षण
- राज्य सरकार को शीघ्र सौंपी जाएगी सर्वे रिपोर्ट

आरक्षण से होगी लाइफ चेंज

मुजफ्फरपुर। रेड लाइट एरिया में रह रही महिलाओं की स्थिति, इनकी जीवन शैली, बच्चों के रहन-सहन, शिक्षा का स्तर, रोजगार संबंधित जानकारी इस सर्वे के माध्यम से एकत्रित की गई है। सरकारी सुविधाओं का कितना लाभ इन्हें अबतक मिल पाया है, रिपोर्ट में यह आधार भी बनाया गया है। परचम की सचिव नसीमा ने बताया कि पूरे बिहार में इनकी आबादी करीब दो लाख है।

सिर्फ मुजफ्फरपुर में इनकी संख्या पांच हजार के लगभग है। आरक्षण से इनका लाइफ चेंज होगा जिससे इनकी सोच का तरीका और फिर सदियों पुरानी रेडलाइट की तकदीर भी बदलेगी। हर समुदाय में महिला सशक्तिकरण के नाम विशेष पैकेज दिया जाता है फिर समाज के सबसे वंचित इस तबके के लिए आरक्षण क्यों नहीं।